बजट भाषण 2021–22
(भाग–क)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं सम्मानित सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2021–22 का बजट पेश करने जा रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, इस सदन में, अपनी सरकार का लगातार सातवां बजट पेश करने का अवसर मुझे मिला है।

2. अध्यक्ष महोदय, यह बजट मैं ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जब हम भारत के लोग अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021–22, जिसके लिए मैं यह बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें हमारे देश की एक सबसे ऐतिहासिक तारीख होगी 15 अगस्त 2021 यानि हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस।

3. मैं आज महसूस कर रहा हूँ, और संभव है इस सदन में बैठा हुआ हर एक सदस्य भी यही महसूस कर रहा होगा, कि हम सब ऋणी हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के, जिनकी निस्वार्थ कुर्बानियों की वजह से आज हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं।जिस सदन में हम सब बैठे हैं, यह सदन, यह कक्ष 1912 से 1926 तक अखंड भारत का संसद भवन रहा है।यह वास्तव में हम सब का सौभाग्य है कि इसी कक्ष में बैठकर आज हम देश की राजधानी, दिल्ली के लोगों की सेवा में चर्चा और निर्णय ले पा रहे हैं।

4. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की तरफ से और इस पूरे सदन की तरफ से, 75 साल पहले हमारी आजादी को संभव करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को, श्रद्धा पूर्वक, शत–शतनमन करते हुए यह बजट प्रस्तुत करता हूँ, और इस भाव के साथ प्रस्तुत करता हूँ कि इसमें उल्लेखित कार्यों और योजनाओं से उन महान शहीदों द्वारा आजाद वतन को लेकर देखे गए सपने के निर्माण में हम कुछकदमों का भी योगदान दे सकें, तो यह हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए आज के इस बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से 'देशभक्ति बजट' के रूप मेंनामांकित भी करना चाहता हूँ।

5. देशभक्ति बजट इसलिए भी, क्योंकि हमारी सरकार ने तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को, अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ, इस पूरे वर्ष धूमधाम से, आन–बान–शान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से,

महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के साथ करने जा रहे हैं और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक, पूरी दिल्ली में उत्सव का माहौल रहेगा। इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा भी में अपने प्रस्तावों में करूंगा। लेकिन यहां मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे लिए आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का अवसर केवल और केवल शहीदों के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करना भर नहीं है।यह एक जिम्मेदारी है पुर्न–अवलोकन की कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 75 साल में कहां से कहां पहुंची है। और इसके बाद के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव यानी जब आजाद हिंदुस्तान 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, उस वक्त हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं। आज के इस देशभक्ति बजट को मैं इंडिया @75 के सेलिब्रेशन के साथ–साथ इंडिया @ 100 की आधारशिला के रूप में भी रखना चाहूंगा।

6. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 6 साल में जो काम हुआ है, और जिसे आगे बढ़ाने के लिए आज मैं 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' का सातवां बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' में मात्र अगले वित्त वर्ष या अगले कुछ वर्षों के लिए ही नहीं बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है, इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति की एक प्रेरक शक्ति बनकर खड़ा होगा। और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। जिस तरह 1947 के आजाद भारत की रचना में दिल्ली, स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की धुरी बनी हुई थी उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 के शिक्षित और समर्थ राष्ट्र की धुरी भी दिल्ली ही बनेगी।उस वक्त की चुनौतियां थी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और सत्ता में बने रहने के लिए देश के व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण। आज अंग्रेज नहीं है लेकिन राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहने के लिए व्यापारियों, मजदूरों और किसानों का शोषण किसी न किसी रूप में आज भी जारी है।

दिल्ली का आर्थिक परिदृश्य : 1947 –2022

7. अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 वर्षों में मेरे बजट वक्तव्य में परंपरा रही है कि मैं सदन के समक्ष दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ। सामान्यतः ये आंकड़े हर वर्ष, वर्तमान और आगामी वित्त वर्ष से संबंधित आंकड़े और अनुमान होते हैं। मैं आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर खड़े होकर, आज आपकी अनुमति से, मेरे वक्तव्य के इस भाग में दिल्ली के पिछले 75 वर्षों के आर्थिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त रोशनी डालना चाहता हूँ।

8. माननीय अध्यक्ष महोदय, 1901 में हमारी दिल्ली, कुल चार लाख की आबादी का, एक छोटा सा शहर थी। 1911 में जब अंग्रेजों ने इसे देश की राजधानी बनाया तो उसके बाद यहां की आबादी थोड़ी–थोड़ी बढ़ना शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई 1941 से 1951 के दशक में, विशेषकर बंटवारे के समय जब पाकिस्तान से लाखों परिवारों ने भारत में आकर दिल्ली को अपना आशियाना बनाया। 1947 में जिस वक्त देश को आजादी मिली थी उस वक्त यहां की आबादी 6.96 लाख थी। 1951 की जनगणना में यह बढ़कर 17.44 लाख पहुंच गई थी। पिछले 75 वर्षों में देश की राजधानी होने के गौरव को आगे बढ़ाते हुए, हम दिल्लीवासियों की संख्या करीब दो करोड़ पहुंच चुकी है। इस ग्रोथ को देखते हुए 2047 तक दिल्ली की आबादी लगभग 3.28 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। आज इस बजट में, 2047 में इतनी बड़ी आबादी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सम्मान से जीने के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी, उनकी अभी से तैयारी की नींव के प्रस्ताव भी रखूंगा।

9. अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद से दिल्ली में जीडीपी के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार के लिए यह संभव भी नहीं रहा होगा कि दिल्ली के लोगों के विकास के लिए अलग से जीडीपी का हिसाब किताब रखते। वर्तमान व्यवस्था के तहत सरकार बनने के बाद से यह आंकड़े उपलब्ध है। 1993–94 में दिल्ली की राज्य जीडीपी 20,992 करोड़ रूपये थी जो कि बहुत उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्तमान में 7,98,310 करोड़ रूपये पर पहुंच चुकी है। इसी तरह 1993–94 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 18,967 रूपये थी (स्थिर मूल्यों पर), जो 2019–20 में 2,74,671 रूपये पहुंच चुकी है जोकि देश में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2020–21 में प्रचलित मूल्यों पर बढ़कर 3,54,004 रूपये हो गई है।

10. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान वित वर्ष (2020–21) में, 1,27,768 रूपये के राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.77 गुणा अधिक है।

11. वर्ष 2020–21 के दौरान दिल्ली की जीएसडीपी में (प्रचलित मूल्यों पर) 3.92% और (स्थिर मूल्यों पर) 5.68% की कमी, कोविड महामारी और इसके रोकथाम के लिए किए गए उपायों का असर दर्शाती है।

12. दिल्ली ने अन्य राज्यों की तुलना में काफी तेजी से और बेहतर प्रगति की है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार, दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को और उनकी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने के लिए दूरदर्शिता से काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे नागरिक की प्रति व्यक्ति आय के बराबर होनी चाहिए। इसे संभव बनाने के लिए हमें अपने नागरिकों की आय में लगभग 16 गुना की वृद्धि करनी होगी जो एक मुश्किल लक्ष्य तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है।

13. अध्यक्ष महोदय, 1973–94 के बीच में दिल्ली की 50 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे थी। 2011–12 के पूरवर्ती योजना आयोग के अनुसार यह घटकर 9.9 प्रतिशत रह गई थी। पिछले 6 वर्षों में जिस तरह हमारी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को निशुल्क पानी, निशुल्क बिजली, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और विशेषकर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई है, इन सब के परिणाम में प्रत्येक परिवार की लगभग 30,000 रूपये प्रतिवर्ष की बचत हो रही है, जिसका असर उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप से पड़ेगा।

वर्ष 2020–21 के लिए संशोधित अनुमान

14. महोदय, मौजूदा वित्त वर्ष (2020–21) के लिए 59,000 करोड़ रूपये का संशोधित अनुमान प्रस्तावित है, जबकि 65,000 करोड़ रूपये का बजट अनुमान अनुमोदित है। 59,000 करोड़ रूपये का संशोधित बजट अनुमान पिछले वर्ष (2019–20) में व्यय किए गए 51,186 करोड़ रूपये से 15.26 प्रतिशत अधिक है। 59,000 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान में 46,215 करोड़ रूपये Revenue Expenditure और 12,785 करोड़ रूपये Capital Expenditure के तहत हैं। Capital Expenditure, (2020–21 में अनुमोदित) 16,930 करोड़ रूपये के BE से घटकर RE में 12,785 करोड़ रूपये पर आ गया है, इसकी वजह कोरोना महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन के कारण Capital Works में धीमापन आना है।

15. इसी तरह Establishment and Other के तहत इस साल BE में 35,500 करोड़ रूपये से बढ़कर RE में 35,900 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, इसके पीछे मुख्य वजह कोरोना संबंधी व्यय है। RE 2020–21 में योजनाओ/परियोजनाओं के लिए 23,100 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, जबकि BE में इनके लिए 29,500 करोड़ रूपये अनुमोदित किए गए थे।

16. महोदय, Excellent & Effective Financial Management कुशल और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के जरिए हमने अपने बकाया ऋण को मार्च 2020 तक 31,135 करोड़ रूपये पर रखा है। दिल्ली का बकाया ऋण वर्ष 2014–15 में 5.90% से घटकर वर्ष 2019–20 में जीएसडीपी के 3.74% हो गया है। 2020–21 के बारे में रिजर्व बैंक के राज्य वित्त संबंधी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का Loan–GSDP ratio देश के अन्य सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

पूरक अनुदान मांग 2020–21

17. महोदय, वर्ष 2020–21 के दौरान RE में 891 करोड़ 87 लाख 40 हजार रूपये के Supplementary Demands की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं सदन का अनुमोदन चाहता हूं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमान

18. महोदय, हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कुल व्यय 30,940 करोड़ रूपये था। मैंने अपना पहला पूर्ण बजट जून 2015 में पेश किया था, जिसमें 37,750 करोड़ रूपये का अनुमानित व्यय था। वर्ष दर वर्ष हम इनोवेटिव स्कीमों, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शहरी सेवाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाओं के जरिए अपना बजट बढ़ाते गए।

19. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत हर्ष के साथ मैं अब वर्ष 2021–22 के लिए 69,000 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित कर रहा हूँ जो 2014–15 में 30,940 करोड़ रूपये की व्यय राशि के दोगुणे से भी अधिक है। यह जानना अत्यंत सुखद रहेगा कि हमारी सरकार की अवधि में स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो दिल्लीवासियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर हमारी सरकार के विशेष ध्यान को दर्शाती है।

20. बजटीय आवंटन के जरिए दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय (Per Capita Expenditure) 2015–16 के 19,218 रूपये से बढ़कर इस साल 33,173 रूपये होने का अनुमान है।

21. 69,000 करोड़ रूपये के बजट अनुमान में 31,200 करोड़ रूपये Expenditure के लिए 37,800 करोड़ रूपये स्कीम और प्रोजेक्ट के लिए हैं। 69,000 करोड़ रूपये के बजट अनुमान 2021–22 में 51,799 करोड़ रूपये Revenue के तहत और 17,201 करोड़ रूपये Capital के तहत रखे गए हैं। 2020–21 के BE में 16,930 करोड़ रूपये Capital और 48,070 करोड़ रूपये Revenue के तहत थे। अगले साल के BE में, वर्तमान वर्ष के BE की तुलना में, Capital में 2% की बढोतरी हुई है, जबकि Revenue 8% बढ़ा है। 2021–22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रूपये का Capital 2014–15 में 7,430 करोड़ रूपये के Capital से दोगुणे से भी अधिक है।

22. वर्ष 2021–22 का प्रस्तावित बजट अनुमान 69,000 करोड़ रूपये का है जो वर्ष 2020–21 के 65,000 करोड़ रूपये के बजट अनुमान से 6.15% अधिक और 2020–21 के संशोधित अनुमान से लगभग 17% से अधिक है।

23. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 69,000 करोड़ रूपये के प्रस्तावित बजट के लिए, 43,000 करोड़ रूपये कर राजस्व से, 1,000 करोड़ रूपये गैर कर राजस्व से, 325 करोड़ रूपये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9,285 करोड़ रूपये लघु बचत ऋण से, 1,000 करोड़ रूपये के पूंजीगत प्राप्तियों से, 6,000 करोड़ रूपये जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 2,088 करोड़ रूपये केंद्र प्रायोजित योजना से, केवल 657 करोड़ रूपये भारत सरकार की अनुदान सहायता से और शेष राशि, प्रारंभिक शेष (ओपनिंग बैलेंस) से जुटाई जाएगी।

<u>स्थानीय निकायों को वित्तीय सहयोग</u>

24. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय निकायों को 4,367 करोड़ रूपये का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,298 करोड़ रूपये स्थानीय निकायों द्वारा योजनाओ/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध राशि के रूप में होंगे और 2,069 करोड़ रूपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (BTA) के रूप में होंगे।

25. इसके अलावा स्थानीय निकायों को 1,805 करोड़ रूपये स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क में हिस्से के रुप में उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार इस प्रकार स्थानीय निकायों को बजट अनुमान 2021–22 में 6,172 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दे रही है।

2021–22 की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं

26. अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा जो वर्ष 2021–22 के बजट का अभिन्न हिस्सा हैं।

आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर देषभक्ति बजट

27. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि आजादी की सालगिरह की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी वर्ष देशभक्ति के वातावरण से ओत–प्रोत रहेगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया 75 वर्ष पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से ही, यानी आगामी 12 मार्च से ही, दिल्ली में देशभक्ति से ओत–प्रोत भव्य आयोजनों की श्रंखला शुरू हो जाएगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन–बान–शान के साथ मनाएगी। इस क्रम में देशभक्ति बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ।

28. 12 मार्च से शुरू हो रहे देशभक्तिपूर्ण आयोजनों की श्रंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आजादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली के विजन को लेकर देश के अलग–अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

29. आजादी की लड़ाई में सरदार शहीद भगत सिंह का जीवन और भारत को लेकर देखे गये उनके सपने आज भी देश के नौजवानो के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होने अपनी जेर्लडायरी में लिखा था – 'अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका करना जरूरी है।'

आजादी के 75वें वर्ष में शहीद भगत सिंह के प्रेरक जीवन पर कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है ताकि देश की वर्तमान युवाशक्ति उनके जीवन से और प्रेरणा ले सके। और इस भाव के साथ जी सकें –

हम मरेंगे भी तो, दुनिया में जिंदगी के लिए
सबकों जीना सिखां जायेंगे, मरते–मरते
ये ना समझो, भगत फांसी पर लटकाया गया
सैंकड़ों भगत बना जायेंगे, मरते मरते

30. इसी तरह भारत की आजादी से लेकर आजाद भारत की रूपरेखा बनाने का काम बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर ने जिस तरह किया वह भी अपने आप में संघर्ष, देशभक्ति और दूरदर्शिता की अद्वितीय मिसाल है। बाबा साहेब के लिखे संविधान की बदौलत ही आज हम ऐसे हिन्दुस्तान में जी रहे हैं जहां जात–पात का भेदभाव करना अमानवीय और असंवैधानिक माना जाता है। बाबा साहेब के प्रेरक जीवन और उनके सपनों के संविधान व हिन्दुस्तान को आज की युवा पीढ़ी तक ले जाने के लिए इस अवसर पर अलग से कार्यक्रम होंगे जिसके लिए बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। हमारा मकसद है कि आजादी के 75वें वर्ष में बाबा साहेब को याद करते हुए हर हिन्दुस्तानी यह कहते हुए पाया जाये –

रूतबा मेरे सर को, तेरे संविधान से मिला है।
ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है।।
औरों को जो मिला है, मुकद्दर से मिला है।
हमें तो मुकद्दर भी, तेरे संविधान से मिला है।।

31. आजाद भारत की 75 साल की यात्रा में हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज– हमारा तिरंगा। मेरा प्रस्ताव है कि इस महान अवसर पर हम अपनी दिल्ली के आसमान को तिरंगे से सजाएं। हम जब दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से गुजरते हैं तो 200 फीट की ऊंचाई पर हवा में लहराते वृह्द आकार तिरंगे को देखकर हम सब का मन हर बार देशभक्ति के रोमांच से भर जाता है। हाल ही में हमने द्वारका स्थित दिल्ली के नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में लगभग 160 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया था। मेरा प्रस्ताव है कि आजादी के 75 वर्ष में सिर्फ चुनिंदा जगहों पर नहीं बल्कि दिल्ली में रहने वाला हर नागरिक अपने घर से अगर थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो वह उस भाव से ओत–प्रोत हुए बिना घर वापस ना लौट सके। इसलिए सरकार पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार लहराते हुए तिरंगे स्थापित करेगी। इन 500 तिरंगों के साथ हम अपनी पूरी दिल्ली को आजादी के 75वें साल में इस तरह सजाएंगे कि आप दिल्ली में भले ही एक या दो किलोमीटर भी किसी सड़क से होकर गुजरें तो आपकी नजरें अपने दाएं या बाएं किसी न किसी तिरंगे को सम्मान से देखते हुए गुजरें। इसके लिए बजट में 45 करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव है।

32. आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए 'देशभक्ति पाठ्यक्रम' की शुरूआत करने जा रही है। इसके तहत रोजाना एक पीरीयड देशभक्ति की क्लास का होगा। इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जायेगा कि हर बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, देश की एकता के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति प्रेम और सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़ा–लिखा आदमी ऐसा कट्टर देश भक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पर बैठे तो रिश्वत लेना तो दूर, एक ट्रेफिक रैड–लाईट तोड़ने पर भी वह खुद अपनी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर सके। हर पढ़ा–लिखा बच्चा महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आये, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ समझे ही नहीं, बखूबी निभाये भी। वह आपसी भाई–चारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति ही देखे। ऐसा देशभक्त नागरिक हम स्कूलों में तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं।

33. गांधी जी से लेकर बाबा साहेब तक, भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की परिकल्पना एक सुशिक्षित राष्ट्र के रूप में की थी। आजादी के बाद नेहरू जी के समय से ही शिक्षा पर काम हुआ है। देश में आईआईटी, आईआईएम, ऐम्स आदि संस्थानों सहित अनेकों विश्वविद्यालय और स्कूल खोले गये, लेकिन ये प्रयास देश की 5 प्रतिशत आबादी को ही अच्छी ऐजुकेशन दिलाने में कामयाब हो पाये। देश की 95 प्रतिशत आबादी आजादी के 75वें वर्ष में भी शिक्षा के उस स्तर तक नहीं पहुंच पायी है जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालजी लगातार इस बात को दोहराते हैं कि हमें शिक्षा को जन–आंदोलन बनाने की जरूरत है। आजादी के 75वें वर्ष में हम इसकी शुरूआत दिल्ली से करेंगे। हम पढ़े–लिखें और सफल लाखों युवाओं को, उन छात्रों की मदद के लिए तैयार करेंगे, जो संसाधन अथवा सूचना के अभाव में जूझ रहें हैं। इसके लिए 'यूथ फोर एजुकेशन' नाम से एक 'मेंटरशिप वालिंयटर' प्रोग्राम इस साल से शुरू किये जाने की योजना है।

34. हमारे बच्चों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करने के लिए, हम दिल्ली में एक नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्मड फोर्सिस प्रिपेरटरी अकादमी शुरू किये जाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं है। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल खोलेंगे। इसके साथ ही दिल्ली आर्मड फोर्सिस प्रिपेरटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों को उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ–साथ एनडीए और सेना में भर्ती के लिए भी तैयार किया जायेगा।

35. दिल्ली सरकार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए, बहादुरी से लड़ने वाले शहीद सिपाहियों के परिवार के सम्मान एवं मदद के लिए एक करोड़ रूपये की राशि देने की योजना शुरू की थी। इसके लिए इस वर्ष 2021–22 में 26 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

36. हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हमारे देश में हुए मन और शरीर पर हुए अनुसंधान रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के आधार पर, उस वक्त जब दुनिया में आधुनिक प्रयोगशालाएं भी नहीं थी, उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान की उन गहराइयों पर अनुसंधान कर लिये थे जिन्हें आज की आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी समझना संभव नहीं हो सका है। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को 'ध्यान और योग' की परंपरा का नाम दिया था। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों वर्षो में दुनिया भर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान 'ध्यान और योग' के रूप में उपलब्ध कराया है। मैंने लॉस एंजिल्स के वीडियो देखें जहां हजारों लोग हर सप्ताह योग और ध्यान करने के लिए आते हैं। हमारे यहां एक–दो दिन के कार्यक्रम के रूप में योग को जीवन में उतारने के कार्यक्रम तो मैंने चलते देखे हैं लेकिन सरकार के स्तर पर, समाज को जोड़ कर निरंतर रूप से, ध्यान और योग को सामान्य जन को उपलब्ध कराने की योजना का अभाव ही रहा है। जिसके कारण जरूरत और जिज्ञासा होने के बावजूद एक आम नागरिक को योग और ध्यान का वांछित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की अलग–अलग कालोनियों में नागरिकों की मांग पर उन्हे ध्यान व योग के इंसट्रक्टर्स उपलब्ध कराये जायेगें। इन ध्यान व योगा इंसट्रक्टर्स को दिल्ली सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए अलग से 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।

37. अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल तक के आजाद हिन्दुस्तान में भारतीय गीत–संगीत और कलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें वर्ष में 'फैस्टिवल ऑफ इंडिया' और 'इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फैस्टिवल' के तहत भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इनका थीम आजादी के आंदोलन से लेकर 75 साल तक की आजाद यात्रा और 100 साल तक का सपना हो, ऐसी हमारी योजना है।

38. दिल्ली सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि अपने बुजुर्ग नागरिकों के सम्मान व सुविधाओं की पूरी व्यवस्था हमारे शहर में उपलब्ध हो। बुजुर्गों के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। आजादी की हीरक जयंती के वर्ष में हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे भूल सकते हैं। 75वें वर्ष के आयोजनो में एक महत्वपूर्ण कदम यह भी

होगा कि हम अपने 75वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने के लिए पूरी दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली में सक्रिय विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों के साथ मिल कर आयोजित होंगें। इसके लिए अलग से 2 करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

39. अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ उन प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो वर्ष 2021–22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है –

स्वास्थ्य सेवाएं

40. 2020 सारी दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम रहा। दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा भी दौर आयेगा, लेकिन हमारे शायर वक्त से आगे चलते हैं। बशीर बद्र साहेब ने कोरोना के दौर के लिए एडवांस में ही शेर लिख दिया था –

कोई हाथ भी न मिलायेगा, गर गले मिलोगे तपाक से।
ये नये मिजाज का शहर है, जरा फांसले से मिला करो।।

शायर की तरह ही शायद दिल्ली सरकार भी जाने–अनजाने में ऐसे दौर की तैयारी कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में निछले 6 वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति ने ही दिल्ली के लिए कोरोना महामारी के दौरान सफल प्रबंधन को संभव बनाया।

41. आजादी के बाद, 1951 के पहले जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उस समय दिल्ली में कुल 12 सरकारी अस्पताल थे और कुल मिलाकर 17 डिसपेंसरी थी। इस समय दिल्ली में 38 मल्टी–स्पेशलिटी अस्पताल, 181 एलोपैथिक औषधालय, 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 27 पॉलीक्लिनिक, 60 सीड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 46 आयुर्वेदिक, 22 यूनानी, 107 होम्योपैथिक औषधालय, 78 डे–शेल्टर होम्स, 311 नाइट–शेल्टर होम्स को कवर करने वाली 22 मोबाइल क्लीनिक और 61 स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। महोदय, मैं इन सब संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं– डॉक्टर नर्स और अन्य सभी अस्पताल कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने महीनों तक, 24 घंटे दिल्लीवासियों और अन्य राज्यों से भी यहां इलाज कराने आये लोगों की अथक सेवा की और उन्हें निर्बाध चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई। उनका योगदान इस महामारी पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण रहा।

42. यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता थी कि दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी, कोविड के दौरान चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत देख, उससे सबक लिया और समय रहते कोविड प्रबंधन के लिए 'होम आइसोलेशन' की नई अवधारणा को उन्होने दिल्ली में शुरू किया। इसके तहत पूरी तरह से स्वस्थ कोविड मरीजों को घर पर ही, चिकित्सकों की ऑनलाइन निगरानी में रखा गया। देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ही शुरू कराया और इसके तहत जरूरतमंद रोगियों को निशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराना शुरू हुआ। होम आइसोलेशन और प्लाज्मा बैंक की इनोवेटिव व्यवस्थाओं को इसके बाद देश में ही नहीं दुनिया भर में स्वीकार किया गया और उसको सराहना मिली।

43. अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए आशा की एक नई किरण जगी है। हालांकि दिल्ली की जनसंख्या और इसके फैलाव को देखते हुए सबको वैक्सीन लगाना एक कठिन कार्य है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। दिल्ली में कोरोना टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 को लागू किया गया। आरंभिक चरणों में करीब 6,00,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति योद्धाओं को कवर करते हुए अगले चरण में 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठजन और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण का कार्य शुरू हो चुका है। वर्तमान में सरकार के पास रोजाना 45,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता है जिसे बढ़ाकर अगले कुछ दिनों में 60,000 कर दिया जायेगा।

44. कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः बाजार में 250 रूपये में उपलब्ध होगी लेकिन हमारी दिल्ली में ऐसे भी परिवार हैं जिनके मन में डर होगा कि मैं एक महीने की तनख्वाह से अपने परिवार के लिए पूरे महीने का राशन खरीदूं या पूरे परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन लगवाउं। महोदय, आजादी के 75वें वर्ष में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में नहीं होना चाहिए। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। इस नई योजना 'आम आदमी निशुल्क कोविड वैक्सीन' के लिए मैं 50 करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

45. कोविड से मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए, दिल्ली सरकार ने विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 1,293 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है। यह परियोजनाएं हैं– ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर और विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया स्वरूप देना आदि। नए अस्पतालों और नया स्वरूप देने का कार्य पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14,000 से अधिक की बढ़ोतरी होगी।

46. बुराड़ी में 768 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे कोविड के लिए 450 बिस्तरों के साथ खोल दिया गया है। इसी प्रकार अंबेडकर नगर अस्पताल भी जुलाई 2020 से कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। द्वारका में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल 1,241 बिस्तरों की क्षमता के साथ अगले वर्ष से काम करना शुरू कर देगा।

47. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी को छोटी–छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक की नई अवधारणा शुरू की थी। आज दिल्ली के विभिन्न मोहल्लों में लोग अपने आस–पास, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपनी छोटी–छोटी बीमारियों के लिए उन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पहले या तो लंबी लाइनों में लगकर सरकारी अस्पतालों में पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता था या फिर मोटे पैसे खर्च करके प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता था।

48. इस दिशा में एक नया और बेहद क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मैं अगले वर्ष से महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक – 'महिला मोहल्ला क्लिनिक' शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी मातायें और बहने, खुल कर अपने हैल्थ इस्यूस के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती हैं। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है तो अपने आस–पास खुद स्पेसिलिस्ट ढूंढ लेती है। लेकिन मिडिल क्लास और लोअर इनकम परिवारों में वो कभी भी महिला रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती। यह हमारे समाज का एक सच है कि महिलाएं अपनी बीमारियों की काफी उपेक्षा करती हैं। इसका नतीजा यह होता है की बहुत सारी महिलाएं अपनी कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसी के साथ जीती रहती हैं। दिल्ली सरकार अब यह जिम्मेदारी निभायेगी कि दिल्ली की हर महिला के आस–पास एक 'महिला मोहल्ला क्लिनिक' हो और उसमें महिला रोग विशेषज्ञ की सेवायें और संबंधित बीमारियों के टेस्ट इत्यादि भी निशुल्क उपलब्ध हों। पहले चरण में दिल्ली के अलग–अलग हिस्सों में 100 'महिला मोहल्ला क्लिनिक'शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे क्रमशः बढ़ाकर हर एक वार्ड में कम से कम एक क्लिनिक तक ले जाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यह अपनी आधी आबादी को सम्मानपूर्वक स्वस्थ रखने की दिशा में उठाया गया, 75 साल की आजादी के इतिहास में, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा और इस कदम को उठाने के लिए आजादी की 75वीं सालगिरह के वर्ष से उचित और क्या समय हो सकता है।

49. स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और नई महत्वपूर्ण शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से आजादी के 75वें वर्ष में की जा रही है। वह है – दिल्ली के हर एक नागरिक को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जायेगा। इसके साथ ही दिल्ली में ऑनलाइन हेल्थ इनफॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (HIMS) स्थापित किया जायेगा। इसमें दिल्ली के नागरिकों की बीमारी, इलाज, टेस्ट रिपोर्ट, दवाइयां

आदि के विवरण का डेटाबेस उपलब्ध रहेगा। सरकार की योजना है कि दिल्ली के हर एक नागरिक को एक ऐसा हेल्थ कार्ड बना कर दिया जाए कि उसे जब भी अपने इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़े तो अपना पुराना रिकॉर्ड, टेस्ट, दवाइयों आदि का विवरण साथ लेकर जाने की जरूरत ही ना पड़े, यह सारी सूचनाएं पहले से ही डेटाबेस में डॉक्टर के पास ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। वह केवल अपना कार्ड लेकर डॉक्टर के पास जाये। पहले चरण में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों, पॉली–क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि को इस ऑनलाइन हेल्थ इनफॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली में आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से स्वास्थ्य देखभाल तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इससे जियो टैगिंग के साथ रोगियों की पहचान और ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। इस प्रणाली के शुरू होने से मरीजों के परिवारों की अनुवांशिक बीमारियों को जानने, और उसके आधार पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

50. दिल्ली में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागरिकों को तुरंत और सुरक्षित इलाज के लिए शुरू की गई 'दिल्ली के फरिश्ते योजना', जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाता है तो उसे पुरस्कार स्वरूप 2,000 रूपये की राशि दी जाती है, और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसका इलाज का खर्चा सरकार उठाती है, यह योजना बेहद सफल रही है और इसकी वजह से 10,600 नागरिकों की जान बचाई जा सकी है। इसकी तारीफ राष्ट्रीय व अंतर–राष्ट्रीय स्तर पर हुई है।

51. इसी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले वह नागरिक, जिनका कोई बड़ा टेस्ट होना है जैसे कि एमआरआई, सिटी स्कैन इत्यादि, और सरकारी सुविधाओं में अगर लाइन लंबी है, तो यह महंगे टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों अथवा केंद्रों से मुफ्त कराए जा सकते हैं। इसी प्रकार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होना है और सरकारी सिस्टम में मरीजों की अधिक संख्या के कारण उसके ऑपरेशन में एक महीने से ज्यादा का समय लग रहा है तो'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के तहत उसके ऑपरेशन की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में कराई जा सकती है और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा उठाया जाता है। इन दूरदर्शी योजनाओं की बदौलत जहां एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का भार कम हुआ है, वहीं आम जनता को जरूरी इलाज समय रहते मिल सका है।

52. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर इलाज, हर एक नागरिक का अधिकार है और आजादी के 75वें वर्ष में हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकी हर एक नागरिक अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त हो सके।

53. महोदय, मैं वर्ष 2021–22 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड रूपये के बजट का प्रावधान करता हूँ, जो कुल बजट का 14 प्रतिशत है। इसमें 1,293 करोड रूपये पूंजीगत परियोजनाओं के लिए शामिल है। इसमें 5,192 करोड रूपये स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए हैं।

शिक्षा

54. अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बातें रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही है और आज हम जहां खड़े हैं वहां से, आजादी के 75 साल से शुरू करके आजादी के 100 साल तक कहां पहुंचना है, इस संबंध में कुछ योजनाओं को भी रखूंगा। आजादी के बाद 1951 में हुए पहले जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक आजादी के वक्त दिल्ली में सरकारी, गैर सरकारी, नगर निगम, एडिड आदि सब मिलाकर 619 स्कूल थे, इनमें भी ज्यादातर संख्या प्राइमरी स्कूलों की थी, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी तो केवल 62 स्कूलों में ही थी। आज दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की कुल मिलाकर संख्या 5,691 है।

55. महोदय, शिक्षा पर किया गया काम 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस' के विकास सिद्धांत की आधारशिला रही है। सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार लगभग 25 प्रतिशत की राशि का आवंटन शिक्षा के लिए रखना, शिक्षा में हमारे विश्वास का साक्षी है।हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकोंकी देश और दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से ट्रेनिंग के बाद, पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों के नतीजे 98 प्रतिशत पहुंच गए। इतना ही नहीं हमारे बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का भी एक रिकॉर्ड बनाया। हमारे ऐसे भी सरकारी स्कूल रहे हैं जहां एक ही स्कूल से 5 छात्र इस साल सीधे आईआईटी पहुंचे। एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों का नीट का एग्जाम पास करना भी इसी तरह का एक नया रिकॉर्ड है। शिक्षा में नवाचार से प्रभावित होकर नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर वन सरकारी स्कूल है।

56. अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच पढ़ाई लिखाई का अच्छा वातावरण, और शानदार नतीजे। इसके बाद अब हमें शिक्षा की गुणवत्ता की ओर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए हैप्पीनेस की रोजाना क्लास शुरू की है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी के भावों को वैज्ञानिक ढंग से पहचानने में सफल हो रहे हैं। हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत रोजाना करीब16 लाखबच्चे अपनी क्लास की शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन के साथ करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना मेडीटेशन का यह

प्रयोग अपने आप में अनूठा है। हैप्पीनेस कार्यक्रम में बढती अंतर्राष्ट्रीय रूचि को देखते हुए इसकी नॉलिज शेयरिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेल की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

57. इसी तरह 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 'एंत्रप्रन्योरशिप मांइडसैट' पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क ट्रैकिंग और सेल्फ मैनेजमेंट जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स विकसित करना। एंत्रप्रन्योरशिप कार्यक्रम के तहत इस वर्ष हम 11वीं और 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए दो हजार रूपये प्रति बच्चे की सीड–मनी उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को अवसर दिए जाएंगे कि वह अकेले या छोटे–छोटे समूहों में बिजनेस आइडिया बनाएं, उसे अपनी क्लास और अपने अध्यापकों के सामने प्रस्तुत करें, स्कूल से पास बिजनेस आइडिया को हर एक स्कूल के लिए अलग से बने एंत्रप्रन्योरस के एक पैनल के सामने पेश किया जाएगा, अगर यहां से भी पास होता है तो फिर सरकार उस आइडिया को सीड–मनी से दो हजार रूपये प्रति बच्चे के हिसाब से फंड करेगी। इनमें से सफल आईडियास को बाद में एग्जीबिशन के माध्यम से पूरी दिल्ली के सामने रखा जाएगा और बेहतरीन आईडियास और उनकी सफलता के बिजनेस मॉडल्स को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

58. अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति पाठ्यक्रम, सैनिक स्कूल एवं अकादमी का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 बड़े कदम उठा रही है। पहला है नर्सरी से आठवीं तक के लिए नया सिलेबस तैयार करना, दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा–परीक्षा बोर्ड स्थापित करना, और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना।

59. नर्सरी से आठवीं तक की क्लासेज के लिए नए पाठ्यक्रम के आधार पर नया सिलेबस तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। इस साल जारी की गई नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी स्कूल एजुकेशन का अहम अंग माना गया है। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार के पिछले बजट में, नई शिक्षा नीति के आने से पहले ही मैंने इसकी घोषणा कर दी थी और हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को मेन–स्ट्रीम एजुकेशन में लाने का काम शुरू भी कर दिया है। नए सिलेबस में प्राइमरी क्लास से ही बच्चे को रटने की जगह, उसके व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जाएगा।

60. दिल्ली का अपना परीक्षा बोर्ड शुरू करने के पीछे भी यही मकसद है कि अभी तक जो पढ़ाई रटने के आधार पर होती हैं, उसे बच्चों की अपने विषयों को समझने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बनाया जा सके।दिल्ली केबिनेट ने बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड तीन लक्ष्य पूरे करेगा – 1. हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त

हों और आने वाले समय में हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधो पर उठाने को तैयार हों, 2. हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, और 3. यह बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार करेगा।

61. यह बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई सुनिश्चित करेगा। हम इसमें इस साल 20–25 सरकारी स्कूलों को शामिल करेंगे। और हमें भरोसा है कि 4–5 साल में सारे सरकारी और निजी स्कूल स्वैच्छासे इसमें शामिल होना चाहेंगे।

62. इसी तरह स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाने के पीछे भी यही मकसद है। अलग–अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को बेहतरीन सुविधाओं के साथ नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में एक्सीलेंस स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देकर पढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत दिल्ली के अलग–अलग हिस्सों में9वीं से 12वीं क्लास के 100 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस खोले जाएंगे, इसमें वर्तमान प्रतिभा विकास विद्यालय और 5 साल पहले खोले गए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को भी शामिल किया जाएगा।

63. देश की प्रतिभाओं को चिन्हित करना और उन्हें पूरे संसाधन लगाकर दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं के सामने मुकाबले में खड़े करना हमारे लिए देशभक्ति की राजनीति है। 75 वर्ष पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियोंकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आजाद हवा में हैं, हमारी तरफ से देशभक्ति की यही राजनीति उन महान अंदोलनकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।

64. अध्यक्ष महोदय, कोविड की महामारी ने, हमें मजबूरी में ही सही, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करना सिखाया है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हमारे अध्यापकों ने बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के, ऑनलाइन शिक्षण को सच करके दिखाया। इसमें विशेष उल्लेख मैं ऐसे अध्यापकों का करना चाहूंगा जिन्होंने संभवतः जिंदगी में स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया होगा लेकिन जब वक्त पड़ा तो उन्होंने भी अपने बच्चों या अपने स्कूलों में नई पीढ़ी के अध्यापकों से तुरंत प्रशिक्षण लेकर तकनीकी का इस्तेमाल सीखा और लगभग 1 साल तक अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया। कोविड की वैक्सीन आ चुकी है और यह बीमारी आज नहीं तो कल एक बीते कल की बात हो ही जाएगी। लेकिन यह हमें जो सिखा गई है उसे हमें आगे लेकर जाना है।यह हमें शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल से भी किस हद तक शिक्षा संभव है इसकी साक्षी बना कर गई है।

65. इसलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे– वह है वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल। यानी ऐसा स्कूल जिसमें चार–दीवारियां नहीं होगी,

कोई बिल्डिंग नहीं होगी, लेकिन बच्चे होंगें, अध्यापक होंगे, रेगुलर पढ़ाई होगी, परीक्षाएं होंगी और पढ़ाई पूरी भी होगी। यह अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा और संभवतः दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल होगा। इस स्कूल की डिजाइनिंग पर काम शुरू कर दिया गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से यह अपना काम करना शुरू कर दें। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ–साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सभी बच्चों को "anywhere living, anytime learning, anytime testing" की अवधारणा के तहत सीखने का अवसर देना चाहते हैं।

66. इसके साथ ही नई स्कूल बिल्डिंग बनाने, नए कमरे बनवाने और स्कूलों में सीसीटीवी लगवाने के कार्य, जो कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों और आर्थिक कारणों से धीमे हो गये थे, उन्हें तेजी से शुरू कर दिया गया है। इनमें से कईअपने अंतिम चरण में है। शिक्षकों के आईआईएम, कैंब्रिज, हार्वर्ड, फिनलैंड, सिंगापुर आदि में प्रशिक्षण की भी जो योजना पिछले वर्ष की परिस्थितियों में अमल नहीं हो पाई थी उन्हें इस वर्ष पुनः चालू किया जाएगा।

67. अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में आजादी के बाद से दिल्ली में गुणवत्ता के लिहाज से तो शानदार काम हुआ लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से उच्च शिक्षा के अवसर हर बच्चे को उपलब्ध कराने में हम पिछले 75 साल में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि पिछले 6 वर्षों में विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली में हायर एजुकेशन की सीटों में 36.42 प्रतिशत और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 66.44 प्रतिशत सीटों की वृद्धि हुई है। अभी और भी बहुत कुछ किया जाना है। गुरू गोबिंद सिंह आईपी विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर का निर्माण कार्य मई 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है। धीरपुर और रोहिणी में अम्बेडकर विश्वविद्यालय का नया परिसर सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा जिससे विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में लगभग 8,500 की बढोतरी होगी।

68. हायर टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में, स्किल एवं एंत्रप्रन्योरशिपयूनिवर्सिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है।स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इस वर्ष अपना काम शुरू कर देगी।

69. नई शिक्षा नीति के बाद हमें देश में टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत जोर–शोर से काम करना होगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन के स्तर पर ही 4 साल की टीचर ट्रेनिंग का बी.एड कोर्स लाने का प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार इसके लिए अलग से एक टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी। इस यूनिवर्सिटी का काम होगा देश और दुनिया के बेहतरीन टीचर्स तैयार करने वाली यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर, देश के लिए एक से एक बेहतर टीचर्स तैयार करना।

70. इसी तरह दिल्ली सरकार आने वाले समय में कानून की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नई दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की भी तैयारी कर रही है।इससे कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को नए अवसर मिलेंगे।

71. अंग्रेजी में अच्छी तरह बातचीत करने में समर्थ होना विद्यार्थियों के लिए हमेशा से एक दुखती रग रहा है। अंग्रेजी बोलने की क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए एक योजना प्रस्तावित की है। यह योजना उन्हें रोजगार की तलाश या उच्चतर शिक्षा में एडमिशन के वास्ते बाहर निकलने के लिए अंग्रेजी भाषा में उनकी क्षमता विकसित करेगी। इस योजना को इंगलिश स्पीकिंग के कोर्स कराने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिल करचलाया जायेगा। इसमें अंग्रेजी बोलने के साथ–साथ बॉडी लेंग्वेज और पर्सनेल्टी डेवलेपमेंट पर भी काम होगा। तीन महीने की अवधि के लिए नियमित क्लासरूम शिक्षा और स्व–शिक्षा मॉड्यूल के द्वारा लगभग 5 से 6 लाख विद्यार्थियों के इस योजना के तहत आने की संभावना है।

72. उच्च शिक्षा निदेशालय दिल्ली से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को दस लाख तक के ऐजुकेशन लोन पर गांरटी प्रदान करता है ताकि किसी बच्चे की उच्च शिक्षा पैसे के अभाव में बीच में न छूटे। इसी के साथ 6 लाख से कम आय के परिवार के बच्चों को दिल्ली सरकार की तरफ से फीस का 100 प्रतिशत तक फेलोशिप के रूप में दिया जाता है। ये दोनो योजनायें अगले साल भी जारी रहेंगी।

73. अध्यक्ष महोदय, देश में नई शिक्षा नीति जारी की गई है। इसमें बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिनमें दिल्ली सरकार पिछले 6 साल में, पहले ही काम शुरू कर चुकी है। मुझे खुशी है कि नई शिक्षा नीति में दिल्ली के शिक्षा में किये हुये कार्यों और प्रयोगों को शामिल किया गया है। मैं स्वयं अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकार के साथ प्रो. के. कस्तूरीरंगन जी से मार्गदर्शन के लिए बंगलौर जाकर मिला। मैं उनका आभारी हूँ कि वो इस नीति को दिल्ली में लागू करने में हमारी मदद कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए हमे दिल्ली में शिक्षा के 50 साल पूराने कानून – दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट1973 और करीब 100 साल पुराने कानून

दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 में बदलाव करने होंगे। ये दोनो कानून नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं से मेल नहीं खाते हैं। हमने केन्द्र सरकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रावधानो को संशोधित करने की मांग की है और दिल्ली के लिये नया दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट भी तैयार करना शुरू कर दिया है।

74. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगले वित वर्ष के लिए शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रूपये आवटिंत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि पिछले 6 बजटों का अनुकरण करते हुए इस वर्ष भी शिक्षा का बजट कुल बजट का लगभग एक चौथाई है।

खेल

75. दिल्ली में आज देश का सबसे बेहतरीन स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रकचर खड़ा हो गया है। हमने दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में भी और विशेषकर गांव देहात के इलाकों में विश्वस्तरीय खेल सुविधायें विकसित की हैं। दिल्ली में 1951 में पहले एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, उसके बाद 1982 में फिर से एशियन गेम्स का आयोजन हुआ। 2010 में मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप और कॉमनवैल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। दिल्ली में अब हमने खेल प्रतिभाओं और सुविधाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए और उन्हे विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए स्पोर्टस यूनिवसिर्टी बनायी है। हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में इन्टरनैशनल मैडल विनिंग चैम्पियन्स तैयार करें।

76. आज जब मैं आजादी की 75वीं सालगिरह की दहलीज पर देशभक्ति बजट इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ तो खेल को लेकर एक और बड़ा सपना, इस उद्‌देश्य के साथ कि भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हमें यह पूरा करना है, भी इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ। यह सपना है कि दिल्ली में ओलपिंक खेलों का आयोजन हो। 1896 में एथेन से शुरू होकर अबतक ओलंपिक की मशाल कभी दिल्ली में आकर नहीं ठहरी। अगले – 32वें ओलंपिक गेम्स टोकियो में आयोजित होने हैं। इसके बाद के अगले तीन ओलंपिक खेलों के होस्ट सिटीज भी तय हो चुके हैं। हमारी सरकार नई खेल यूनिवसिर्टी के माध्यम से खेल सुविधाओं को और खेल प्रतियोगिताओं के प्रति वातावरण को इस स्तर तक लाने का लक्ष्य रखती है ताकि हम 2048 के 39वें ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए आवेदन कर सकें। यह समय अभी दूर लग सकता है लेकिन 2048 के करीब 10 साल पहले हमें इसकी बिडिंग करनी होगी और उसके पहले 15 साल पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रकचर बनाने, वातावरण बनाने और तब तक की प्रतियोगिताओं में अपने खिलाड़ियों को मैडल लाने में लगेंगे। परन्तु यह उम्मीद और यह सपना आज आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देखना बहुत जरूरी है।

आवास एवं शहरी विकास

77. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए सड़क, नाली, पार्क, आदि का निर्माण से लेकर, वहां पर सीवर डलवाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने आदि के कार्यों पर लगातार जोर दे रही है। हमारी सरकार के पहले तक यह काम केवल दिल्ली की 895 अनधिकृत कॉलोनियों तक ही थोड़े बहुत स्तर पर कराए जाते रहे थे लेकिन 2015 के बाद से दिल्ली की हर एक अनधिकृ त कॉलोनी और झुग्गी बस्ती में उपरोक्त सुविधाएं देने का काम तेजी से हुआ है। अब तक दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1345 में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है अथवा प्रगति पर है।इन कालोनियों में विकास के लिए मैं 1,550 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान करता हूँ।

78. डयूसिब के सराहनीय प्रयासों के कारण एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित कर दिया गया है। यहां 21,586 वैस्टर्न सीटस के साथ 674 जन सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं।झुग्गी बस्तियों में 619 बस्तियों में 10,16,531 मीटर सीमेंट कंक्रीट के फुटपाथ और ढाई सौ किलोमीटर नालियों का निर्माण किया गया है तथा यहां रह रहे लोगों के लिए 20 नए बस्ती विकास केंद्र बनाए गए हैं।

79. हमारी सरकार 'जहां झुग्गी वहां मकान' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुल्तानपुरी के नजदीक की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वालों के लिए 1,060 मकान आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा देव नगर करोल बाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहू–मंजिलें मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

80. महोदय में 2021 में आवास और शहरी विकास की योजनाओं व परियोजनाओं के लिए 5,328 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता

81. दिल्ली में प्रत्येक घर को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का वायदा पूरा करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटस में 9 प्रयोगशालाएं 24 घंटे काम कर रही हैं। पानी की आपूर्ति का हिसाब–किताब रखने के लिए 3,170 बल्क–फ्लोमीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और 121 बल्क–फ्लोमीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

82. अनधिकृत कॉलोनियों में पाइप से पानी की सप्लाई के नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है और मौजूदा समय में यह सेवा 93 प्रतिशत परिवारों को लगभग 14,500 किलोमीटर पाइप लाइन के जरिए पहुंचा दी गई है। पाइप लाइन से पानी की सप्लाई के नेटवर्क में 1,622 अनाधिकृत कॉलोनियों को कवर कर लिया गया है।केवल 113 कॉलोनी को छोड़कर जिन्हें अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं मिला है या जो वन क्षेत्र में आते हैं।अगले 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से सभी अनाधिकृत कालोनियों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। अनधिकृत कालोनियों में पाइप से पानी की सप्लाई के नेटवर्क का विस्तार कर दिया गया है और 79 प्रतिशत आबादी इस नेटवर्क के दायरे में आ गई है।

83. जिन कॉलोनियों में सीवर की लाइन पिछले वर्षों में डाली गई हैं वहां पर 'मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना' के अंतर्गत 4.88 लाख सीवर कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की अपनी लागत पर नियमित किए गए और यह योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी।

84. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 प्रतिष्ठानों में से 585 में रेन–वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली लगा दी है और शेष काम 2021 के मानसून से पहले ही पूरा हो जाने की उम्मीद है।

85. इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का काम भी अब लगभग 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है। एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से अब अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह साफ किया जा सकेगा।

86. महोदय, मैं 2021–22 में दिल्ली जल बोर्ड में योजनाओ, कार्यक्रमो और परियोजनाओं के लिये 3,274 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूं। इसमें 600 करोड़ रुपये 20 किलोलीटर निशुल्क पानी सब्सिडी योजना के लिये है जिससे प्रतिमाह लगभग 6 लाख लाभार्थियों को लाभ हो रहा है।

पर्यावरण

87. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण प्रदूषण हमारे समय की सबसे खतरनाक वैश्विक बीमारियों में से एक है। पिछले 75 साल में तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदूषण बढ़ा ही है। लेकिन जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हो तो हम सब चाहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की बीमारी भी बीते कल की बात हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में 360–डिग्री अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को यथासंभव विस्तार देना, निर्माण स्थलों पर एंटी–स्मोग गन के इस्तेमाल को जरूरी बनाना, पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार बायो डी–कंपोजर के इस्तेमाल को पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रोत्साहन देना, मैकेनिकल रोड़ स्वीपर लगाना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, सॉलिड वेस्ट

मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से मैनेज करना, खुले में कूड़ा–पत्तियां आदि जलाने की प्रथा पर रोक लगाना, थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करना आदि ऐसे कई कदम है जो दिल्ली सरकार ने पर्यावरण की बहुमुखी सुरक्षा के लिए उठाए हैं।

88. लेकिन इसमें सबसे बड़ा कदम है – देश ही नहीं संभवतः दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दिल्ली में लागू करना। यह पॉलिसी अगस्त 2020 से लागू कर दी गई है। इसके चलते दिल्लीइलेक्ट्रिक–व्हीकल की राजधानी भी बन गई है। इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में इलेक्ट्रिक–व्हीकल की संख्या कुल 0.2 प्रतिशत होती थी। इसके बाद से 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में खरीदे गए हैं। और अगर केवल पिछले 3 महीने के आंकड़ों की तुलना करें तो कुल 1,18,482 खरीदे गए नए वाहनों में से2,621इलेक्ट्रिक–व्हीकल खरीदे गए। यानी नई पॉलिसी के आते ही इसका असर दिखने लगा है और इलेक्ट्रिक वाहनों का शेयर 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत पहुंच गया है। यह ई–व्हीकल पॉलिसी की सफलता का एक बड़ा संकेत है। हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होंगे।

89. दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जहां हर तरह के ई–वाहनों के लिए रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है और पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। जल्दी ही इनकी संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। इसमें लंदन की तर्ज पर रैपिड चार्जिंग प्वाइंट्स भी बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर कम से कम एक ई–चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो हमारी दिल्ली वाहनों के प्रदूषण से 100 प्रतिशत आजाद हो चुकी होगी।

90. अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण रेफरेंस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में, जब तक मोटर वाहनों का अविष्कार नहीं हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बड़ी आबादी घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल करती थी। निशुल्क ऑपरेशन के लिए हर रात, रास्तों से घोड़े की लीद को हटाना उस समय का सबसे बड़ा काम था। 1898 में न्यूयॉर्क में मोटर कार का आगमन हुआ। 30 जुलाई 1898 को मोटर वाहनों के इस्तेमाल के पक्ष में दुनिया का पहला विज्ञापन छापा गया।इसमें लिखा था *"Get rid of HORSES and save costs, care and anxiety for the horse. Driving motor vehicle costs about half a cent per mile. Motor chariot of Winton is the best vehicle of its kind ever made. Designed to be*

gorgeous, strong, yet with a simple and elegant finish. Easily sustainable. Speed of 3 to 20 miles per hour (4.8 to 32 km/h). The combustion engine is simple and powerful. Odorless, without vibration. Wheel damping wire. Pneumatic tires. Ball bearings."

91. यह बहुत पुरानी बात हो चुकी है लेकिन मैंने यह बात सदन के समक्ष इसलिए रखी ताकि इस हल्के–फुल्के माहौल में हम गंभीरता से समझ सकें कि अगले 25 साल में दिल्ली के संपूर्ण यातायात को इलेक्ट्रिक–व्हीकल में बदलना एक मुश्किल सपना जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल कितना ही हो लेकिन जरूरी बहुत है। पर आज इस सदन में एक सपने के रूप में, कुछ योजनाओं के रूप में हम इसकी नींव रख रहे हैं।

92. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ई–बसों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1,300 ई–बसें सड़कों पर लाने की तैयारी कर रही है इनमें से डीटीसी की 300 ई–बसों के टेंडर हो चुके हैं और यह इसी वर्ष दिसंबर तक सड़कों पर उतर जाएंगी। 1,000 नई ई–बसें क्लस्टर स्कीम के तहत अगले साल के मध्य तक सड़कों पर आ जाएंगी।

93. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए दिल्ली में पहली बार लगभग एक साल के अंदर 1,600 बसों का काफिला जुड़ा है और इस साल सितंबर तक इसमें 1,000 और बसें जुड़ जाएंगी। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में वर्तमान में 6,693 बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काफिले में हैं, इतनी बड़ी बस–फ्लीट दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई। इस साल 1,000 बसें और जोड़ने के बाद तो यह संख्या 7693 पहुंच जाएगी।सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 11,000 बस–फ्लीट का लक्ष्य लेकर चल रही है।

94. दिल्ली में प्रदूषण पर काबू करने के लिए जहां निर्माण स्थलों पर एंटी–स्मॉग गन लगाना आवश्यक कर दिया गया है वहीं दो स्मॉग टावर दिल्ली में लगाने का काम अंतिम चरण में है। इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली और कानपुर के साथ मिलकर वायु, जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिए रियल टाइम एसेसमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है।

95. दिल्ली के ग्रीन कवर को बचाए रखने और इससे लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में भी सरकार ने सफलता हासिल की है देश की पहली 'ट्रीट्रान्सप्लांटेशन पॉलिसी' दिल्ली में लागू हुई है। इसका मकसद है कि दिल्ली में पेड़ केवल और केवल उस परिस्थिति में काटे जायें जब इसके अलावा कहीं कोई उपाय ना बचा हो। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में किसी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने की जरूरत पड़ेगी उनमें से कम से कम 80 प्रतिशत को ज्यों–का–त्यों दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाना जरूरी होगा। इसके साथ ही हर एक काटे गए अथवा ट्रांसप्लांट

किए गए पेड़ की जगह 10 नए पेड़ लगाने की शर्त भी रहेगी। दिल्ली में वर्तमान में ग्रीन कवर बढ़कर 21.88 प्रतिशत हो गया है जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

96. इन सब प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हम प्रदूषण की चुनौती से निपटने में जरूर कामयाब होंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ व शुद्ध वातावरण उपलब्ध करा कर जाएंगे।

परिवहन

97. अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किए काम का कुछ जिक्र मैं पर्यावरण पर बात करते हुए कर चुका हूँ। लेकिन परिवहन पर बात करते हुए मैं दोहराना चाहूंगा कि वर्तमान समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई सभी नई बसों में सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली का प्रावधान है। दिल्ली में जमीन की अनुपलब्धता, बसों की खरीद और परिचालन के लिए एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार की दूरदर्शिता से वसंत विहार और हरी नगर में बहुस्तरीय बस डिपो के निर्माण का अब रास्ता खुल गया है और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी(एनबीसीसी) के साथ मिलकर इन डिपो का निर्माण किया जा रहा है।

98. दिल्ली में बसों से यात्रा करने को एक अच्छा अनुभव बनाने के लिए नए बस क्यू–शेल्टर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। सरकार 1,397 बस क्यू–शेल्टर नये डिजाइन के साथ बना रही है।

99. लास्ट–माइल–कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए सरकार ने 95,353 ई–रिक्शा का पंजीकरण किया है। साथ ही 174 नॉन एसी मेट्रो फीडर बसें 32 रूटस पर चलाई जा रही है।

100. दिल्ली में दिल्ली मेट्रो आज शहर की लाईफ–लाईन बन चुकी है। दिसम्बर 2002 में शुरू होने के बाद मात्र 18 वर्ष में आज दिल्ली मेट्रो की 10 कलर कोडिड लाईन्स हैं, 254 स्टेशन्स हैं और 350 किलोमीटर की पटरियां हैं। चौथे चरण की योजना में 108 किलोमीटर और 78 नये स्टेशन्स अभी पाईपलाईन में हैं। आजादी के 75वें साल में हमारी उपलब्धियों पर बात करते हुए हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि मैट्रो हमारी दिल्ली की एक बड़ी उपलब्धि है। लंदन में 1863 में मैट्रोकी लाईने बिछाई गयी और आज भी कुल 400 किलोमीटर कवर करती है। टोकियो सब–वे, जिसकी शुरूआत 1927 में हुई, 304 किलोमीटर कवर करती है। न्यूयॉर्क सिटी मैट्रो जिसकी शुरूआत 1904 में हुई, 1,000 किलोमीटर कवर करती है। दिल्ली में मैट्रो शुरू करने में हम एक सदी जरूर पीछे रहे लेकिन मात्र 18 वर्ष में हमने सबसे तेजी से बढ़ती हुई मैट्रो लाईन के रूप में इसे स्थापित किया है और आज दिल्ली मैट्रो रोजाना 56 लाख लोगों को यात्रा कराती है।

मैट्रो का विस्तार और विकास 'केजरीवाल मॉडल आफ गर्वनेंस' का अहम हिस्सा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम आजादी के 100वें वर्ष में होगे तो हमारी मैट्रो दुनिया की सबसे बडी लाईन और सबसे ज्यादा पैसेजर्स को ले जाने वाली मैट्रो के रूप में अपनी पहचान बना चुकी होगी।

101. दिल्ली मेट्रो के फेज–4 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 71.26 लाख हो जाएगी। फेज–1 के तहत 65.1 किलोमीटर और फेज–2 के तहत 124.93 किलोमीटर मेट्रो लाइन पूरी कर ली गई है। फेज–3, अतिरिक्त कॉरिडर और एनसीआर विस्तार में 160 किलोमीटररूट की लंबाई है, जिसमें से 157. 94 किलोमीटर चालू भी हो गया है। मयूर विहार पॉकेट–1 से त्रिलोकपुरी खंड तक का शेष कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार कार्य सितंबर 2021 में पूरा होगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज–4 के सभी 6 कॉरिडर्स के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने मेट्रो फेज–4 परियोजना के प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडरो का अनुमोदन किया है।

102. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की महिलाओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सुविधा वर्ष 2021–22 में भी जारी रहेगी।

103. मैं परिवहन विभाग और रोड एंव ब्रिज के लिए 9394करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव 2021–22 में करता हूँ।

सड़क अवसंरचना

104. महोदय, मैंने दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन में अतिरिक्त 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा अपने पिछले बजट भाषण में की थी। लगभग 1,32,000 कैमरे, कमांड कंट्रोल सेंटर (सीसीसी) सहित लगाए जा चुके हैं और काम कर रहे हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु वर्ष 2021–22 के लिए 200 करोड़ रुपयेका प्रस्ताव करता हूँ।

105. हमारी सरकार लोगों को निशुल्क वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 7,000 हॉट–स्पॉट लगाने का काम पूरा हो चुका है और नागरिकों को निशुल्क वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

106. शहर में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से 2021–22 में कई परियोजनाएं पूरी किए जाने के लिए निर्धारित हैं। आश्रम चौक पर अंडर पास का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा हो जाने से मथुरा रोड (निजामुद्दीन से बदरपुर बार्डर तक) और आश्रम क्रासिंग पर यातायात सुगम हो जाएगा। यात्रा–समय, प्रदूषण–स्तर में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। महोदय, मैं वर्ष 2021–22 में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

107. आश्रम फ्लाईओवर के डीएनडी तक विस्तार का काम दिसंबर 2021 तक पूरा होगा। इस फ्लाईओवर और सब–वे के बन जाने से नोएडा और लाजपत नगर तथा आईटीओ और लाजपत नगर तक सड़क का उपयोग करने वालों को आसानी होगी। मैं, वर्ष 2021–22 में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

108. दो परियोजनाओं का निर्माण कार्य – वजीराबाद और आजादपुर के बीच वाहनो के लिए दो अंडरपास और आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार–पथ तथा बसईदारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण कार्य मई 2021 तक पूरा हो जाएगा।

109. पंजाबी बाग फ्लाईओवर से राजागार्डन, ज्वालाहेड़ी मार्केट रेडलाइट से ज्वालापुरी रेडलाइट तक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडर, मुकरबा चौक पर भीड़भाड़ कम करने की स्कीम, बुराड़ी में समानांतर सड़क पर मेन बुराड़ी रोड जंक्शन पर भीड़भाड़ कम करने और खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द तक रेलवे क्रासिंग नंबर एलसी–12 पर आरओबी/आरयूबी के निर्माण की पांच नई परियोजनाओं के निर्माण से इन क्षेत्रों में निर्बाध यातायात में सुधार होगा तथा लोगों का समय और पैसा बचेगा।

110. दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को और आसान बनाने के लिए सरकार की तीन बड़ी योजनायें तैयार हैं और यूटीपैक से मंजूरी के इंतजार में हैं। ये योजनायें हैं – ईस्ट–वेस्ट कॉरिडर, टीकरी से आंनदविहार तक ऐलीवेटिड एंड टनल रोड़, नार्थ–साउथ कॉरिडर, सिगनेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक ऐलीवेटिड एंड टनल रोड़, और तीसरी सिगनेचर ब्रिज से यमुना के समानांतर सराय काले खां तक आउटर रोड़।

111. 7 खंडो के अलावा 500 किलोमीटर सड़कों के सौन्दर्यकरण के काम की भी तैयारी हो चुकी है और इसे इस वर्ष से लागू करना शुरू कर दिया जायेगा।

112. मैं, वर्ष 2021–22 में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

113. महोदय, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांगजनों और सुविधा वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को लेकर काफी सक्रिय है। इसके तहत 8.30 लाख लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जा रही है। मैं, वर्ष 2021–22 में इन लाभार्थियों के लिए 2,710 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ।

114. अध्यक्ष महोदय, कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी–रोटी पर बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम–धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गयी हैं। संकट के इस समय में हमारी सरकार यह अपना फर्ज समझती है कि हम सोच–समझ कर सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की ऐसी योजनायें बनाये जिनसे लोगों को इस विकट संकट में मदद मिले। इसके लिए हमने एक सर्वे भी करवाया जिसमें निकल कर आया कि कोरोना से पहले, फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर 26 प्रतिशत थी, जो कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के लंबे समय के बाद भी, फरवरी 2021 में 40 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलायें जो कुछ काम ढूंढ रहीं हैं उनमें से 40 प्रतिशत को कोई काम नहीं मिल रहा है। इन 40 प्रतिशत महिलाओं में से भी 45 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जिन्होने कम से कम 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की है और इनमें से 60 प्रतिशत महिलाऐ तो 30 वर्ष से कम उम्र की हैं। दिल्ली की इस युवा महिला शक्ति को परिवार और दिल्ली की इकॉनामी में जोड़ना जरूरी है। सरकार ने महिलाओं की इकॉनामी में भूमिका को और मजबूत करने के लिए कुछ नई योजनायें तैयार की हैं। इनमें से प्रमुख हैं – सहेली समन्वय केन्द्र : इसके तहत दिल्ली के अलग–अलग हिस्सों में 500 आंगनवाड़ी हब बनाये जायेंगे। इन्हे सुबह के 4 घंटे आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने के बाद आस–पास के क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं के लिए इन केन्द्रों को उपलब्ध कराया जायेगा। इन केन्द्रों को समृद्धिनाम की सैल्फ–हैल्प–ग्रुप या इंडिविजुअल स्टॉटअप के इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा। यहां पर इनकी माइको–इकॉनामिक एक्टीविटी चलाने की ट्रेनिंग देने, एसएचजी समूह की बैठकों आदि के लिए विशेष व्यवस्थायें होंगी।

115. दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनायें चलाती है जैसे कि लाडली योजना, विधवा–वृद्घावस्था पेंशन, लड़कियों की पढ़ाई व रोजगार के लिए सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, महिला निमार्ण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण योजनायें, इत्यादि, इत्यादि। आमतौर पर गरीब महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में पता नहीं होता या कई बार वे समझ नहीं पाती हैं कि उनके लिए कौन सी स्कीम ठीक रहेगी और कौनसी नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी दिल्ली में 33 महिला सहायता प्रकोष्ठ शुरू करेगी जहां

काउंसलर्स महिलाओं के आमने–सामने बैठ कर उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे।

116. शहर में मादक पद्धार्थों की समस्या से निपटने के लिए सुल्तानपुरी में एक सूर्योदय केन्द्र की शुरूआत करने का प्रयोग सफल रहा। इसे आगे बढ़ाते हुए ड्रग एवं सब–स्टांशियल एबूज रिहैबिलिटेशन के लिए पूरी दिल्ली में अलग–अलग जिलों में इसके केन्द्र खोले जायेंगे।

117. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पर बाबा साहेब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना प्रस्तावित है। डीएसएफडीसी ने 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाले इन शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से शिल्पी हाट बनाने और 5 वर्ष की अवधि के लिए मासिक लीज आधार पर उन्हें दुकानें/थड़ा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

118. सरकार ने दिव्यांग लोगों की शिक्षण और पुनर्वास जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों के लिए पुनर्वास संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी है। 'सुगम्य सहायक योजना' नाम से एक नई पहल दिव्यांग लोगों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत उन्हें सहायक उपकरणों के रूप में मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांग लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा।

119. मैं समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2021–22 में 4,750 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ।

श्रम

120. अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के कल्याण के लिए मानवीय श्रम कानूनों को लागू किया जाना महत्वपूर्ण है। कार्यबल की एक बड़ी संख्या औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर में लगे हैं। ये कानून उनके अधिकारों और कानूनी पात्रताओं की रक्षा करते हैं।

121. दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 के तहत बाधारहित पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया का डिजिटीकरण किया गया है तथा 83,735 नई दुकानें और प्रतिष्ठान, 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्तूबर 2020 तक ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं।

122. स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उपकरणों के लिए ऋण और विवाह के लिए आर्थिक सहायता की 18 योजनाएं दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा लागू की जा रही हैं। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक लगभग 143.41 करोड़ रुपये की राशि उप कर के रूप में संग्रहीत की गई है। लगभग 1,41,169 कामगार 24 जनवरी 2021 तक बोर्ड में पंजीकरण करा चुके हैं। अब तक 43,945 निर्माण कामगारों को कोरोना महामारी के कारण अनुग्रह राहत दी गई है। 28 फरवरी, 2021 तक लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी।

ऊर्जा

123. माननीय महोदय, दिल्ली के नागरिकों को अब चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति मिल रही है। बिजली लोड को नजरअंदाज करते हुए 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल की सरकार की योजना काफी सफल रही है और इसका ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का विकल्प चुना है। 201 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। दिल्ली में 90 प्रतिशत घर बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। सरकार 1984 दंगा पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली खपत पर शत प्रतिशत सब्सिडी देती है।

124. 'विशेष बिजली सब्सिडी योजना' अदालत परिसरों में वकीलों के चैम्बर के लिए भी विस्तारित की गई है। इसी प्रकार दिल्ली में सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है। कृषि कनेक्शन के लिए 105 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच प्रति माह के निर्धारित शुल्क के स्थान पर अब किसानों को 20 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच प्रति माह का भुगतान करना होगा। ये योजनाएं 'सुशासन के केजरीवाल मॉडल' की विशिष्टताएं हैं। महोदय, मैं वर्ष 2021–22 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3,090 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित करता हूँ।

125. महोदय, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति बनाई है, जिसके तहत अधिकांश सरकारी भवनों, स्कूलों, तकनीकी संस्थानों और अदालतों इत्यादि में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया जारी है। जनवरी 2021 तक लगभग 4,664 सौर ऊर्जा इकाई, कुल 193 मेगा वाट की क्षमता के साथ दिल्ली में लगाए जा चुके थे। किसानों ने "मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना" के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है।

126. वितरण कंपनियां अगले 5 वर्ष में, जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों से अनावश्यक केबल और तारों के जाल हटाएगी। हमारी सरकार ने 11 किलोवाट के नेटवर्क को खुली तारों की जगह इंसुलेटिड तार (जगमगाती दिल्ली प्रोग्राम के तहत) बदलने की नई योजना शुरु की है। यह योजना चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके लिए बजट अनुमान 2021–22 में 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

127. मैं बजट अनुमान 2021–22 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,227.40 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ।

व्यापार और उद्योग

128. माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ने 'राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना' के तहत अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। यह रैंकिंग 2018 में 23वीं थी जबकि 2019 में यह 12वें स्थान पर आ गई। ऐसा सुचारू व्यवसाय माहौल सृजित करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के उद्देश्य के साथ लागू किए गए सत्त सुधारों के कारण संभव हुआ है। दिल्ली सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में विभिन्न उपाय किए हैं, इनमें जीएसटी, दुकान प्रतिष्ठान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए पंजीकरण, औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, डिस्कॉम से नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन और दिल्ली जल बोर्ड से पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, एमसीडी में निर्माण परमिट, और पिछले एक वर्ष के दौरान डीपीसीसी से स्थापना और संचालन संबंधी सहमति से संबंधित आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति और प्रोसेसिंग शामिल है। मेरा मानना है कि दिल्ली में व्यवसाय के लिए बेहतर माहौल ने विश्व बैंक की व्यापार संबंधी रैंकिंग 2020 में भारत को 63वां स्थान दिलाने में मदद की है, जबकि 5 वर्ष पहले भारत 142वें स्थान पर था।

129. दिल्ली का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार आरंभ किया गया है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यात का प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को दिया जाएगा, जो अपनी वस्तु और सेवाओं के निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।

130. उद्योग विभाग/डीएसआईआईडीसी द्वारा लीज–होल्ड पर आवंटित औद्योगिक परिसंपत्तियों से जुड़े किसी भी मामले में विलंब से भुगतान पर ब्याज दर 18 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दी गई है। नंगली सकरावती औद्योगिक क्लस्टर को पुनर्विकास के लिए अधिसूचित किया गया है।

131. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सुविधा के लिए समाधान ऑनलाइन पोर्टल शुरु किया गया है। हालांकि इसमे बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण 2,000 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। इनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए और छोटे व्यवसायों के लाभ के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद को, प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में, 11 परिषदों में पुनर्गठित किया गया है, ताकि मध्यस्थता से उनके राजस्व क्षेत्र में आने वाले विवादों का समाधान किया जा सके।

132. दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में एक स्टार्ट–अप केंद्र के रूप में स्थापित हुई है। सरकार लोगों के बीच उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपना खुद का व्यवसाय उपक्रम शुरु करना चाहते हैं। सरकार ने इसके लिए एक मसौदा स्टार्ट–अप नीति तैयार की है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

133. अध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्यटन, कला एवं संस्कृति के संबंध में कुछ प्रस्ताव सदन के समक्ष रखूंगा। लेकिन उसके पहले मशहूर अंग्रेजी फिल्म डैड पोएटस सोसाइटी के एक दृश्य का यहां जिक्र करना चाहूंगा। उस दृश्य में फिल्म का नायक,प्रो. जोन कीटींग, अध्यापक अपने छात्रों से कहता है–*We do not read and write poetry because it is cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Medicine, law, business, engineering..... these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, love.... these are what we stay alive for.* यह दृश्य है तो अंग्रेजी फिल्म का, लेकिन दर्शन विशुद्ध भारतीय है। हम भारत के लोगों ने कला, भाषा, संस्कृति, साहित्य इस सब को जीवन जीने का जरिया नहीं बल्कि जीवन के आनंद का उद्देश्य माना है। इसीलिए हमारे तीज–त्योहार से लेकर तमाम उत्सव कला और संस्कृति से सराबोर होते हैं।

134. दिल्ली सरकार ने पिछले वर्षों में कला, पर्यटन और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कई नई योजनायें लागू की हैं। अगले वर्ष दिल्ली सरकार कई नये प्रोग्राम लेकर आ रही है। इसमें 'फैस्टिवल ऑफ इंडिया' और 'इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फैस्टिवल' का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। देश की सभी भाषाओं की अकादमियां पहले ही बनायी जा चुकी हैं इस वर्ष से ये अकादमियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। दिल्ली में नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ–साथ इस बार देशभक्ति से सराबोर अनेक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

135. 'दिल्ली की दिवाली' का आयोजन पिछले 2 वर्षों से एक ऐसा आकर्षण बन गया है कि अब लोग दिल्ली सरकार के इस आयोजन का इंतजार करते हैं। दिल्ली की दिवाली का आयोजन अगले वर्ष भी पूरी धूमधाम से किया जायेगा।

136. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 'दिल्ली हेरिटेज प्रोमोशन' और 'दिल्ली टूरिज्म सर्किट' नाम की दो नयी योजनायें लेकर आ रही है। दिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांडिंग के लिए पिछले वर्ष में एक नई स्कीम प्रस्तावित की थी जो कोविड के कारण अमल में नहीं आ सकी। इस स्कीम को अब अगले वर्ष लागू किये जाने का प्रस्ताव है। पर्यटनस्थलों पर महिला सुरक्षा के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। इसमें पर्यटन स्थलों के सभी प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, अंधेरे स्थानों को एलईडी प्रकाश से रौशन करने, डीटीटीडीसी के सभी पर्यटन स्थलों पर यूनीफार्म में सुरक्षा गार्ड की तैनाती, विभिन्न पर्यटन स्थलों पर मोबाइल वैन की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं। इसके लिए बजट 2021–22 में 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

137. मैं पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा आदि क्षेत्रोंसे संबंधित परियोजनाओं, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2021–22 में 521 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

138. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण का भाग–ख प्रस्तुत करता हूँ जो राजस्व से संबंधित है।

(भाग–ख)

139. महोदय, कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आई आर्थिक मंदी के असर से मौजूदा वित्त वर्ष में हमारे कर राजस्व में भारी कमी आई है। जनवरी, 2021 तक कर राजस्व संग्रह बजटीय अनुमान की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम हुआ है।

140. 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तब सभी राज्यों को 5 साल के लिए 14 प्रतिशत के ग्रोथ रेट के साथ एश्योर्ड रिवेन्यू का वादा किया गया था। लेकिन कोविड पेनडैमिक के नाम पर केन्द्र सरकार ने इस साल अपना वादा पूरा नहीं किया और इस साल कंपनशेषन की जगह लोन दिया गया है। दिल्ली सरकार के सामने आने वाले समय में दो चुनौतियां रहेंगी– पहली तो केन्द्र सरकार का अपने कंपनसेशन के वादे से मुकरना और दूसरा एश्योर्ड रिवेन्यू की सीमा भी

30 जून 2022 को समाप्त हो जायेगी। इसके बाद राजस्व संग्रह में बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी।

141. हम डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए टैक्स में किसी भी सम्भावित लिकेज को रोकेंगे। इसके लिए हम जीएसटी के बेहतर इंप्लीमेंटेशन की स्टडी भी करा रहे हैं। हमने दिल्ली आने–जाने वाले व्यवसायिक वाहनों पर आरएफआईडी के जरिये नजर रखना शुरू किया है और व्यापारियों के साथ टैक्स के मामलों में SMS से संवाद भी शुरू किया है।

142. दिल्ली में कर–संग्रह बढाने के लिए एक्साईज पॉलिसी में भी व्यापक बदलाव किये जा रहे हैं। इसमें बिना डयूटी शराब की बिक्री पर लगाम लगाने से लेकर दिल्ली में लिक्कर शापिंगको इन्टरनेशनल स्टेंडर्ड तक लाने संबंधित कई नए बदलाव होंगे।

143. अभूतपूर्व परिस्थितियों से निकलने के लिए हमे कई बार अभूतपूर्व कदम ही उठाने की जरूरत पड़ती है। लॉकडाउन के कारण आई मंदी से उबरने और रियल एस्टेट मार्किट को बढावा देने के लिए सरकार ने 6 महीने के लिए सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की कमी लाने का भी फैसला लिया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने हाल ही में कहा था कि शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर/कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अनस्किल्ड वर्कर के लिए सबसे ज्यादा जॉब के अवसर देता है, और इससे गरीबी को रोकने में मदद मिलती है। हमें उम्मीद है कि सर्किल रेट कम करने का सरकार का कदम गरीब लोगों को रोजगार के नए अवसर भी क्रिएट करेगा।

144. हमारा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों की उम्मीदें और विकास की रफ्तार 'केजरीवाल मॉडल ऑफ गर्वनेंस' में थमने नहीं दी जायेगी।

145. अध्यक्ष महोदय अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद के 75 साल में हमारे राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया है, और बहुत कुछ हासिल भी किया है। हमारे लिए यह वक्त उत्सव का भी है और मंथन का भी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दिल्ली के आम आदमी की पर–कैपिटा इनकम को सिंगापुर के बराबर ले जाने के लिए दृढसंकल्प है। साफ हवा, साफ पानी और सरकारी हेल्थ सिस्टम में बेहतरीन मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हर दिल्लीवासी का मूलभूत अधिकार है। हम हर दिल्लीवासी के लिए विश्वस्तरीय स्कूल और उच्च शिक्षा और रिसर्च के अवसर यहीं दिल्ली में ही उपलब्ध कराएंगे। हम दिल्ली में उस दिन की आधारशिला रखना चाहते हैं जब दिल्ली, ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगी।

रॉबर्ट फ्रास्ट के शब्दों में –

"We have promises to keep and miles to gobefore we sleep"

राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा 110 साल पहले कहे गए शब्द आज भी समीचीन है–

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

146. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं बजट सदन के विचार के लिये सौंपता हूँ।